

अपने ग्राहक को जानें ("केवाईसी") और धन शोधन निवारण ("एएमएल") नीति

संस्करण नियंत्रण

संस्करण	निर्माण / संशोधन तिथि	प्रभावी तिथि	संस्करण का विवरण
1	17 अगस्त 2018	20 अगस्त 2018	नया दस्तावेज़
2	25 फरवरी 2019	26 फरवरी 2019	संशोधित दस्तावेज़
3	15 जून 2021	17 जून 2021	संशोधित दस्तावेज़

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना.....	4
भाग १ : (ए) उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर और उनके अर्थ सांविधिक/विनियामक या अन्यथा.....	5 से 6
भाग १ : (बी) नीति में प्रयुक्त परिभाषाएँ.....	7
भाग २ : कंपनी की केवाईसी/एएमएल नीति.....	12
A. पृष्ठभूमि.....	12
B. नीति समीक्षा	12 से 13
C. नीति के उद्देश्य	13
D. दायरा और प्रयोज्यता	13
E. महत्वपूर्ण तत्व.....	13
i. ग्राहक स्वीकृति मानदंड/नीति ("सीएपी")	13 से 14
ii. ग्राहक पहचान प्रक्रिया ("सीआईपी")	14 से 18
iii. जोखिम प्रबंधन.....	18 से 20
iv. लेन-देन की निगरानी	20
F. निरंतर निगरानी प्रक्रिया.....	20 से 21
G. लाभार्थी स्वामी की पहचान.....	21
H. प्रशिक्षण कार्यक्रम.....	21
I. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली.....	21
J. रिकॉर्ड प्रबंधन.....	21 से 22
K. फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट- भारत	22
L. जनरल	22
i. नई प्रौद्योगिकियों का परिचय	22
ii. भारत से बाहर की शाखाओं और सहायक कंपनियों के लिए प्रयोज्यता.....	22
iii. खातों को बंद करना/वित्तपोषण/व्यावसायिक संबंध की समाप्ति.....	22
iv. मौजूदा खातों के लिए केवाईसी	22
v. विविध मुद्दे.....	22 से 23
vi. कंपनी की केवाईसी नीति में अपडेट	23
भाग III अनुलग्नक.....	24
अनुलग्नक 1 ग्राहक पहचान आवश्यकताएँ... सांकेतिक मार्गदर्शन.....	24
अनुलग्नक 2 वित्तीय सेवाओं से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की दृष्टान्त सूची	25

अपने ग्राहक को जानें/धन शोधन निवारण नीति

प्रस्तावना:

1. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) एक अंतर-सरकारी वैश्विक नीति बनाने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली संबंधित अन्य खतरों से निपटने के लिए मानकों को निर्धारित करने और कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसने सिफारिशों की एक श्रृंखला विकसित की है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है। FATF ने सभी AML/CFT प्रणालियों के अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में, जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (RBA) को मजबूत करते हुए 2017 में एक संशोधित मार्गदर्शन जारी किया।
2. इस निकाय के सदस्य के रूप में भारत सरकार ने आरबीआई के साथ कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का कानून बनाया। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 2005 में एक संशोधन और रिकॉर्ड के रखरखाव के नियमों के माध्यम से पीएमएलए के तहत कवर किया गया था।
3. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा (3), जिसे अब तक संशोधित पीएमएलए के रूप में संदर्भित किया गया है, धन शोधन के अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती है और इसे व्यापक और समावेशी तरीके से परिभाषित करती है:
"जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी है या वास्तव में शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा।"
4. 10 मई, 2021 को नवीनतम संशोधित अधिनियम और आरबीआई के नियामक निर्देशों की शब्दावली, वित्तीय संस्थान के संचालन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। काशी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) अपने केंद्रित ग्राहक वर्ग और कड़े स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के बावजूद, अपने संचालन में ऐसे जोखिमों की संवेदनशीलता को पहचानता है। कंपनी यह मानती है कि व्यापार रणनीति को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी और प्रभावी अनुपालन रणनीति अपनाकर सक्रिय रूप से एक अच्छी कॉर्पोरेट नागरिकता प्राप्त की जाती है।
5. जिन ग्राहकों के साथ कंपनी व्यवहार रही रहा है, उनकी स्पष्ट पहचान अच्छी व्यावसायिक समझ है। इसके अलावा, इसकी व्यावसायिक प्रथाओं में एकीकृत करने की आवश्यकता - परिचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुवादित - प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन रणनीति और अनुपालन प्रयास दोनों के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी के उपयोग को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।
6. कंपनी ग्राहक की पहचान, सत्यापन और लेनदेन की चल रही निगरानी की परिचालन व्यावसायिक प्रक्रियाओं में संबंधित अधिकारियों को संबंधित दस्तावेजों की रिपोर्टिंग, रखरखाव और उपलब्धता की प्रासंगिक वैधानिक और नियामक अपेक्षाओं के एकीकरण की अनिवार्यता को भी पहचानती है।
7. कंपनी अपने लक्षित बाजार क्षेत्रों के जोखिम प्रोफाइल के प्रति सचेत है, जो मुख्य रूप से वंचित/अंडरसर्व्ड हैं लेकिन बड़ी व्यावसायिक क्षमता के साथ हैं। इस खंड को वित्तीय पहुंच से वंचित न बने रहने के लिए, जो कंपनी के "बुद्धि वृद्धि समृद्धि" प्रौद्योगिकी और बैंकिंग आदतों में उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के मिशन का एक हिस्सा है। कंपनी वर्तमान में ग्राहक जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप अपने सीमित संसाधनों के साथ कड़े नियमों का पालन करने के लिए आनुपातिक परिचालन पहलों को लागू करेगी।
8. कंपनी यह मानती है कि इस महत्वपूर्ण प्रयास में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना न केवल स्थायी व्यापार रणनीति का एक प्रमुख तत्व है, बल्कि अनुपालन आवश्यकता के रूप में भी है।
9. यह दस्तावेज़, अपने केवाईसी/एएमएल नीति रुख की गणना करते हुए, इस पृष्ठभूमि में जारी किया गया है, जिसकी संरचना इस प्रकार है:

भाग I: (ए) उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर और उनके अर्थ वैधानिक / नियामक या अन्यथा; तथा

(बी) नीति में प्रयुक्त परिभाषाएं।

भाग II: कंपनी का केवाईसी/एएमएल नीतिगत ढांचा; तथा

भाग III: अनुलग्नक

भाग I: (ए) उपयोग किए गए संक्षिप्ताक्षर और उनका अर्थ वैधानिक / नियामक या अन्यथा

नंबर	संक्षेपाक्षर	विवरण
1	ए ए आर	आधार प्रमाणीकरण नियम, 2016
2	एएमएल	एंटी मनी लॉन्ड्रिंग
3	बी ओ	लाभकारी स्वामी
4	बीओआई / बीओपी / एओपी	व्यक्तियों का निकाय / व्यक्तियों का निकाय / व्यक्तियों का संघ
5	सी एपी	ग्राहक स्वीकृति नीति
6	सीडीडी	ग्राहक के लिए उचित परिश्रम
7	CERSAI	भारत के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री
8	सीएफटी	आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला
9	सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी
10	सीआईपी	ग्राहक पहचान प्रक्रिया
11	सीकेवाईसीआर	सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री
12	सीआरएस	सामान्य रिपोर्टिंग मानक
13	सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर
14	सीटीआर	नकद लेनदेन रिपोर्ट
15	डीडी	मनोनीत निदेशक
16	विदेश व्यापार महानिदेशालय	विदेश व्यापार महानिदेशक
17	ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम
18	ईडीडी	एनहैंस ड्यू डेलीजेन्स
19	ई-केवाईसी	इलेक्ट्रॉनिक-अपने ग्राहक को जानें
20	FATCA	विदेशी खाता टैक्स अनुपालन अधिनियम
21	एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
22	एफआईयू-इंडिया	वित्तीय खुफिया इकाई-भारत
23	आई ए	सामान्य बिक्री कर
24	आई डी	आंतरिक लेखा परीक्षा
25	पहचान	पहचान दस्तावेज़
26	आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
27	आई एम पी एस	अंतर सरकारी समझौता
28	छापे	तत्काल भुगतान प्रणाली

29	आईआरएम	एकीकृत जोखिम प्रबंधन
30	केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
31	केवाईसीडी	अपने ग्राहक को जानें निर्देश, 2016
32	एम ओ टी	लेनदेन की निगरानी
33	एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
34	एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
35	एनपीओ	गैर लाभकारी संगठन
36	नरेगा	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
37	ओ डी डी	जारी ड्यू डिलिजेंस
38	ओटीपी	एक बारी पासवर्ड
39	ओवीडी	आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज़
40	पैन	स्थायी खाता संख्या
41	पी ई पी	राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति
42	पीएमएल (एमओआर)	धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005
43	पीएमएलए	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
44	पीओ	प्रधान अधिकारी
45	आर ई	विनियमित संस्थाएं
46	आर एम	जोखिम प्रबंधन
47	आरटीजीएस	रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
48	एसए	छोटा खाता
49	एसडीडी	सरलीकृत कारण परिश्रम
50	सेबी	भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड
51	एसटीआर	संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट
52	यूसीआईसी	विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड
53	टीडीएफओएसबीएसए	(वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016, आधार अधिनियम
54	यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान विकास प्राधिकरण
55	वैट	मूल्य वर्धित कर

भाग I: (बी) नीति में प्रयुक्त परिभाषाएँ:

नंबर	अवधि	अर्थ/परिभाषा
1	आधार संख्या	पहचान और पते के लिए ओवीडी का गठन करने वाले निवासी भारतीय को जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त होने पर यूआईडीएआई द्वारा किसी व्यक्ति को जारी एक पहचान संख्या। (आधार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार)
2	"अधिनियम" और "नियम"	पीएमएलए, 2002 और पीएमएल (एमओआर) नियम, 2005, और उसमें संशोधन।
3	प्रमाणीकरण	आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में, आधार अधिनियम 2016 की धारा 2 की उप-धारा (सी) के तहत परिभाषित प्रक्रिया है
4	लाभकारी स्वामी	प्राकृतिक व्यक्ति जो संबंधित व्यावसायिक संगठन या संस्थाओं और ट्रस्टों सहित व्यक्तियों के संघ को नियंत्रित करता है। कृपया देखें आकृति 1 आकृति 1 लाभकारी स्वामी की पहचान
		<p style="text-align: center;">लाभकारी स्वामी की पहचान (अंततः कानूनी नैसर्गिक व्यक्ति)</p> <p>याहक</p> <p>कंपनी</p> <p>भागीदारी फर्म</p> <p>नैसर्गिक समूह/व्यक्तियों का समूह</p> <p>स्वामित्व का नियंत्रण</p> <p>नियंत्रण रखना</p> <p>अकेले या समूह में या 'एक या अधिक' नैसर्गिक व्यक्तियों के साथ</p> <p>जहां पर कोई कानूनी या नैसर्गिक व्यक्ति नामित नहीं है।</p> <p>25% से ज्यादा शेयर या पूंजी का स्वामित्व</p> <p>25% से ज्यादा लाभ की पात्रता</p> <p>बहुसंख्यक निर्देशकों को नियुक्त करने का अधिकार</p> <p>निम्न के द्वारा प्रबंधन या निधि निर्धारण में नियंत्रण</p> <p>a) शेयर पूंजी/ धारिता</p> <p>b) प्रबंधन अधिकार</p> <p>c) शेयर धारक सहमति/ एग्रीमेंट</p> <p>d) वोटिंग अधिकार</p> <p>पूंजी में 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी</p> <p>मुनाफे में 15% से ज्यादा की हिस्सेदारी</p> <p>पूंजी या संपत्ति में से 15% ज्यादा का स्वामित्व</p> <p>मुनाफे में 15% से ज्यादा की पात्रता</p> <p>कानूनी व्यक्ति जो की वरिष्ठ प्रबंधक की हैसियत रखता है</p> <p>न्यास का निर्माणी</p> <p>न्यासी</p> <p>15% या उसके अधिक हित के साथ न्यास के लाभार्थी</p> <p>न्यास</p> <p>अन्य कोई कानूनी व्यक्ति जो की न्यास के उपर श्रेणीबद्ध नियंत्रण या अधिकार के द्वारा अंतिम रूप से प्रभावी नियंत्रण रखता है</p>
5	बायोमेट्रिक जानकारी	इसमें फोटो, फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन या किसी व्यक्ति की ऐसी अन्य जैविक विशेषताएं शामिल हैं जो एएआर, 2016 द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं। (जैसा कि आधार अधिनियम की धारा 2(जी) में परिभाषित है)
6	सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी	एक या एक से अधिक स्थानों में एक केंद्रीकृत डेटाबेस जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबर होते हैं, साथ ही संबंधित जनसांख्यिकीय जानकारी और ऐसे व्यक्तियों की बायोमेट्रिक जानकारी और उससे संबंधित अन्य जानकारी, (जैसा कि आधार अधिनियम की धारा 2(एच) में परिभाषित है)
7	सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री	ग्राहक के डिजिटल रूप में केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने, संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने और पुनर्प्राप्त करने के लिए एक इकाई।

नंबर	अवधि	अर्थ/परिभाषा
		(जैसा कि एएआर, 2016 के नियम 2(1)(एए) के तहत परिभाषित किया गया है)
8	प्रमाणित प्रति	विनियमित संस्था(आरइ) द्वारा एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अर्थ होगा आधार संख्या के कब्जे के प्रमाण की प्रति की तुलना करना जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज मूल के साथ और आरई के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि पर रिकॉर्ड करना अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार
9	ग्राहक	एक व्यक्ति जो एक विनियमित इकाई (आरई) के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में शामिल व्यक्ति कार्य कर रहा है।
10	ग्राहक ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी)	ग्राहक और लाभार्थी स्वामी की पहचान करना और उनका सत्यापन करना।
11	ग्राहक की पहचान	सीडीडी की प्रक्रिया शुरू करना
12	जनसांख्यिकीय जानकारी	किसी व्यक्ति के नाम, जन्म तिथि, पता और अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित जानकारी शामिल है, जैसा कि आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जाति, धर्म, जाति, जनजाति, जातीयता, पात्रता आय या चिकित्सा इतिहास के रिकॉर्ड, भाषा शामिल नहीं होगी। ; (जैसा कि आधार अधिनियम की धारा 2(के) में परिभाषित है।)
13	मनोनीत निदेशक	पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आरई द्वारा नामित एक व्यक्ति। व्याख्या: इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रबंध निदेशक" और "पूर्णकालिक निदेशक" शब्दों का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में उनके लिए निर्दिष्ट अर्थ होगा। नामित निदेशक का नाम, पदनाम और पता FIU-IND को सूचित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, प्रधान अधिकारी को 'नामित निदेशक' के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।
14	डिजिटल केवाईसी	इसका अर्थ है ग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार के कब्जे का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ जहां ऐसी लाइव फोटो अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार आरई के अधिकृत अधिकारी द्वारा ली जा रही है।
15	डिजिटल हस्ताक्षर	इसका वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (पी) में दिया गया है।
16	नामांकन संख्या	नामांकन आईडी एक 28 अंकों की नामांकन पहचान संख्या है जो आधार के नामांकन के समय निवासियों को आवंटित की जाती है। (जैसा कि आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 की धारा 2(1)(जे) में परिभाषित है)
17	ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा	एक प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधा जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी और आधार संख्या को अनुरोध करने वाली संस्था के माध्यम से आधार संख्या धारक की सहमति से सुरक्षित रूप से जमा किया जाता है, सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है, और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणीकरण लेनदेन से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ ई-केवाईसी डेटा युक्त प्रतिक्रिया देता है; (जैसा कि आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016 में परिभाषित है)
18	समकक्ष ई-दस्तावेज़	का अर्थ है एक दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष, जो इस तरह के दस्तावेज़ के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते को जारी किए गए दस्तावेज़ शामिल हैं (डिजिटल प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) लॉकर सुविधाएं) नियम, 2016
19	पहचान की जानकारी	एक व्यक्ति के संबंध में, व्यक्ति की आधार संख्या, बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी शामिल है; (जैसा कि आधार अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एन) में परिभाषित है)

नंबर	अवधि	अर्थ/परिभाषा
20	आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी)	<ol style="list-style-type: none"> 1. पासपोर्ट, 2. ड्राइविंग लाइसेंस, 3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, 4. राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, 5. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण होता है। <p>जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेज या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों को ओवीडी माना जाएगा: -</p> <ol style="list-style-type: none"> i. उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल) का दो महीने से अधिक पुराना नहीं है; ii. संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद; iii. सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है; iv. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव एण्ड लाइसेंस समझौते; <p>ग्राहक ऊपर निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी जमा करेगा</p> <p>जहां एक विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं होता है, ऐसे मामले में विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।</p> <p>व्याख्या 1.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक दस्तावेज को ओवीडी माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना आधारित हो, जो दर्शाता हो नाम का ऐसा परिवर्तन।</p>
21	व्यक्ति	<ol style="list-style-type: none"> a. एक व्यक्ति, b. एक हिंदू अविभाजित परिवार, c. एक कंपनी, d. एक फर्म, e. व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, f. प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो उपरोक्त व्यक्तियों (ए से ई) में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आता है, और g. उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा (ए से एफ)।
22	प्रधान अधिकारी	आरई द्वारा नामित एक अधिकारी, नियमों के नियम 8 के अनुसार अनुपालन, लेनदेन की निगरानी और जानकारी साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। प्रधान अधिकारी का नाम, पद और पता FIU-IND को सूचित किया जाएगा।
23	निवासी	एक व्यक्ति जो आधार के लिए नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में कुल मिलाकर एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए भारत में रहा हो; (जैसा कि आधार अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (v) के तहत परिभाषित किया गया है)
24	संदिग्ध लेनदेन	<ol style="list-style-type: none"> a. संदेह के उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध की आय इसमें शामिल मूल्य की परवाह किए बिना शामिल हो सकती है, या b. असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में बनाया गया प्रतीत होता है; या c. ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक औचित्य या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; या d. संदेह के उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है। <p>व्याख्या: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेन-देन में ऐसे लेनदेन शामिल हैं जिनमें धन से जुड़े या संबंधित होने का संदेह है, या आतंकवाद, आतंकवादी कृत्यों या आतंकवादी,</p>

नंबर	अवधि	अर्थ/परिभाषा
		आतंकवादी संगठन या आतंकवाद को वित्तपोषित करने या वित्त करने का प्रयास करने वाले लोगों द्वारा उपयोग किया जाना है।
25	लेन - देन	<p>a. खाता खोलना;</p> <p>b. जमा, निकासी, विनिमय या किसी भी मुद्रा में धन का हस्तांतरण, चाहे नकद या चेक, भुगतान आदेश या अन्य उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक माध्यमों से;</p> <p>c. सुरक्षा जमा बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी अन्य रूप का उपयोग;</p> <p>d. किसी भी प्रत्ययी संबंध में प्रवेश करना;</p> <p>e. किसी भी संविदात्मक या अन्य कानूनी दायित्व के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान; या</p> <p>f. कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था की स्थापना या निर्माण।</p>
26	वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)	सीडीडी उद्देश्य के लिए आवश्यक पहचान जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक के साथ निर्बाध, सुरक्षित, लाइव, सूचित-सहमति आधारित ऑडियो-विजुअल बातचीत करके आरई के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा चेहरे की पहचान और ग्राहक उचित परिश्रम के साथ ग्राहक पहचान की एक वैकल्पिक विधि, और स्वतंत्र सत्यापन और प्रक्रिया के ऑडिट ट्रेल को बनाए रखने के माध्यम से ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता का पता लगाना। निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को इस मास्टर निदेश के प्रयोजन के लिए आमने-सामने सीआईपी के समान माना जाएगा।
27	हाँ/नहीं प्रमाणीकरण सुविधा	एक प्रकार की प्रमाणीकरण सुविधा जिसमें पहचान की जानकारी और आधार संख्या को अनुरोध करने वाली संस्था के माध्यम से आधार संख्या धारक की सहमति से सुरक्षित रूप से जमा किया जाता है, फिर सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा के साथ मिलान किया जाता है लेकिन कोई पहचान जानकारी नहीं, और प्राधिकरण डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित गतिविधि के साथ जिसमें "हां" या "नहीं", प्रमाणीकरण लेनदेन से संबंधित अन्य तकनीकी विवरणों के साथ जानकारी देता है। (जैसा कि आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016 में परिभाषित है)
28	ग्राहक	एक व्यक्ति जो एक विनियमित इकाई (आरई) के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में शामिल व्यक्ति कार्य कर रहा है।
29	वॉक-इन ग्राहक	एक व्यक्ति जिसका आरई के साथ खाता-आधारित संबंध नहीं है, लेकिन आरई के साथ लेनदेन करता है।
30	ग्राहक की उचित जांच पड़ताल	"आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों" का उपयोग "पहचान के प्रमाण" और "पते के प्रमाण" के रूप में ग्राहक और लाभकारी स्वामी की पहचान करना और उनका सत्यापन करना।
31	ग्राहक की पहचान	सीडीडी की प्रक्रिया शुरू करना।
32	FATCA	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं या विदेशी संस्थाओं द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें अमेरिकी करदाता पर्याप्त स्वामित्व हित रखते हैं।
33	केवाईसी टेम्पलेट्स	व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए सीकेवाईसीआर को केवाईसी डेटा को एकत्रित करने और रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए तैयार किए गए टेम्पलेट।
34	सामने न आने वाले ग्राहक	जो ग्राहक आरई की शाखा/कार्यालयों में गए बिना या आरई के अधिकारियों से मिले बिना खाता खोलते हैं।
35	सतत निगरानी	खातों में लेनदेन की नियमित निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ग्राहकों के प्रोफाइल और धन के स्रोत के अनुरूप हैं।
36	आवधिक अद्यतन	यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेज, डेटा या जानकारी को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-समय पर मौजूदा रिकॉर्ड की समीक्षा करके अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाता है।

नंबर	अवधि	अर्थ/परिभाषा
37	राजनीतिक रूप से सम्बंधित व्यक्ति	पीईपी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे जाते हैं, उदाहरण के लिए, राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकार/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी, आदि।
38	शेल बैंक	एक बैंक जो एक ऐसे देश में निगमित है जहां उसकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है और किसी भी विनियमित वित्तीय समूह से असंबद्ध है।
39	तार स्थानांतरण	एक बैंक में एक लाभार्थी व्यक्ति को एक राशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक के माध्यम से एक प्रवर्तक व्यक्ति (प्राकृतिक और कानूनी दोनों) की ओर से सीधे या हस्तांतरण की एक श्रृंखला के माध्यम से किया गया लेनदेन।
40	घरेलू और सीमा पार वायर ट्रांसफर	जब प्रवर्तक बैंक और लाभार्थी बैंक एक ही व्यक्ति या एक ही देश में स्थित अलग-अलग व्यक्ति हों, तो ऐसा लेन-देन एक घरेलू वायर ट्रांसफर है, और यदि 'प्रवर्तक बैंक' या 'लाभार्थी बैंक' अलग-अलग देशों में स्थित है तो ऐसा लेन-देन क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर है।

भाग-2 : कंपनी का केवाईसी/एएमएल नीति ढांचा

A. पृष्ठभूमि:

1. समय-समय पर संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निहित शक्तियों के संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2016 में आरबीआई/डीबीआर/2015-16/18 मास्टर निदेश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 तक अद्यतन) के तहत (अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)) निर्देशों के तहत निर्देश जारी किए थे। नियामक संदर्भ उक्त दिशा में निम्नानुसार इंगित किया गया है: -

"धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में, विनियमित संस्थाओं (आरई) को लेन-देन करते समय कुछ ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। खाता-आधारित संबंध स्थापित करना या अन्यथा और उनके लेनदेन की निगरानी करना। आरई धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाएंगे, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जाएगा, जिसमें ऐसे संशोधनों के अनुसरण में जारी किए गए परिचालन निर्देश शामिल हैं।)"

2. काशी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (काशी कैपिटल या कंपनी) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय अर्थव्यवस्था के असंगठित और संगठित दोनों क्षेत्रों में व्यक्तियों, गैर-व्यक्तियों और व्यवसायों को उधार देना है। हमारे ग्राहक इस पैसे का उपयोग अपने एमएसएमई व्यवसायों का विस्तार करने, अपनी व्यावसायिक इकाइयों/स्व-नियोजित व्यवसायों में विविधता लाने और अन्य व्यक्तिगत खर्चों/वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। उपरोक्त निर्देशों के प्रावधान कंपनी पर इन निर्देशों के पैराग्राफ 3 (बी) (xiii) (सी) के तहत विशेष रूप से परिभाषित एक विनियमित इकाई के रूप में लागू होते हैं।
3. यह नीति कंपनी की व्यावसायिक रणनीति के संदर्भ में निर्धारित की गई है जिसमें लक्षित बाजारों, साधारण ऋण उत्पादों, भौगोलिक सामंजस्य और सबसे ऊपर, लक्षित ग्राहकों की प्रोफाइल को कवर किया गया है, जो ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में कम कवरेज वाले समुदायों से हैं। कंपनी की व्यावसायिक रणनीति की प्रकृति ग्राहकों की पहचान के आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्र में ग्राहकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छोटे ऋणों को प्रोत्साहित करती है जो मुख्य रूप से संस्थागत तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में जानकारी पर निर्भर करती है, स्वेच्छा से दी गयी जानकारी प्रकट होती है और क्षेत्र में आमने-सामने बातचीत के दौरान सत्यापित होती है। कंपनी के ऋण कार्य के चयन, मूल्यांकन, रिपोर्टिंग, निगरानी और अनुवर्ती पहलुओं में कंपनी की परिचालन प्रक्रियाओं में व्यवसाय और नियामक हितों की रक्षा करना अंतर्निहित है।
4. केवाईसी/एएमएल पर पीएमएलए और आरबीआई के मास्टर निर्देश के तहत दिशानिर्देशों के लिए, कंपनी ने एक प्रधान अधिकारी नियुक्त किया है। वर्तमान "प्रधान अधिकारी" श्री बिप्लब पॉल हैं। पीएमएल अधिनियम 2002 के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, "नामित निदेशक" श्री रोहित कुमार सिंह होंगे।
5. नियामक के तहत लेनदेन की निगरानी और जानकारी साझा करने और रिपोर्टिंग करने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संगठनात्मक संदर्भ।
6. संक्षेप में, केवाईसी अनुपालन के केंद्र में लाभकारी स्वामी की पहचान है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी के उपयोग को रोकने के लिए एक उचित और प्रभावी ग्राहक उचित परिश्रम प्रक्रिया और निरंतर आधार पर लेनदेन की निगरानी के माध्यम से स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक व्यक्ति है/हैं।

B. नीति समीक्षा:

7. यह नीति एक जीवंत दस्तावेज है जिसकी दो साल में एक बार समीक्षा की जानी चाहिए या प्रचलित व्यवसाय/अनुपालन वातावरण/तत्वों के अनुसार कम अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए।
8. जब भी इस नीति की समीक्षा की आवश्यकता होती है, पहलकर्ता एक अनुरोध के साथ प्रधान अधिकारी से संपर्क करेगा, इसे नामित निदेशक को कॉपी करेगा और अपेक्षित निर्णय के लिए प्रासंगिक जानकारी/डेटा जमा करेगा। निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए संबंधित समिति द्वारा संशोधनों की सिफारिश करने से पहले सभी संशोधनों को जोखिम प्रबंधन समिति / लेखा परीक्षा समिति को उनकी सहमति के लिए भेजा जाएगा।

C. नीति उद्देश्य:

9. पूर्वागामी के संदर्भ में, कंपनी की "अपने ग्राहक को जानो नीति" (इसके बाद इस नीति में "केवाईसी नीति" के रूप में संदर्भित) तैयार की गई है। नीति के व्यापक उद्देश्य हैं: -
 - (i) अपने ग्राहकों, उनके व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा की बेहतर समझ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक साधन के रूप में कंपनी या उसके संसाधनों के उपयोग को रोकें;
 - (ii) एक संगठन संरचना स्थापित करें जो प्रासंगिक नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करे, जिसमें शामिल हैं:

- a. एक प्रधान अधिकारी का पद;
 - b. वैधानिक और नियामक प्रावधानों के अनुपालन के प्रयोजनों के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की परिभाषा;
 - c. प्रबंधन के विभिन्न स्तरों के अनुपालन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदारियों का आवंटन;
 - d. यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित कर्मचारी केवाईसी/एएमएल/सीएफटी प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं;
 - e. बोर्ड को रिपोर्ट करने, लेखा परीक्षा और स्वतंत्र समीक्षा के माध्यम से केवाईसी/एएमएल अनुपालन की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना;
- (iii) निवारक उपायों को शामिल करें जिनमें शामिल हैं:
- f. व्यापार नीति/रणनीति में केवाईसी सिद्धांतों के तत्वों सहित ग्राहक स्वीकृति नीति;
 - g. ग्राहक पहचान प्रक्रिया;
 - h. लेनदेन की निगरानी;
 - i. निर्धारित नियामक मानदंडों के आधार पर ग्राहकों के वर्गीकरण के माध्यम से जोखिम प्रबंधन;
- (iv) उधार देने के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के लिए विश्वसनीय ग्राहक डेटा प्राप्त करने के लिए बिना बाहरी दबाव के माध्यम से संरचित प्रक्रियाओं के माध्यम से लाभकारी मालिकों की पहचान पर दिशानिर्देश प्रदान करें।
- (v) दिशानिर्देश में खातों की वास्तविक पहचान और लाभकारी स्वामित्व, धन के स्रोत, ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, ग्राहक के व्यवसाय के संबंध में खाते में संचालन की तर्कसंगतता आदि का निर्धारण करने के लिए उचित प्रयास करना अनिवार्य है।
- (vi) कंपनी को धन शोधन के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए एक निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करें, जिसमें शामिल हैं:
- a. आरबीआई के केवाईसीडी, 2016 के पैरा (4) के तहत आवश्यक निदेशक को नामित करें।
 - b. पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट करने के लिए "वरिष्ठ प्रबंधन" को परिभाषित करना;
 - c. उचित अधिकारियों को लेनदेन की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक "प्रधान अधिकारी" नामित करें।
- (vii) व्यावसायिक निर्णय लेना, प्रभावी जोखिम प्रबंधन और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना; केवाईसी नीति के साथ-साथ व्यापार रणनीति के परिचालन स्तर के कार्यान्वयन को साथ-साथ करने के लिए नियामक दिशानिर्देशों और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप दिशानिर्देश प्रदान करें।

D. दायरा और प्रयोज्यता:

10. केवाईसी नीति कंपनी भर में लागू होगी, अर्थात् सभी शाखाओं और प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालयों में, जहां कहीं भी किसी भी तरह से ग्राहक व्यवहार होता है।
11. ये दिशानिर्देश बॉक-इन ग्राहकों के साथ-साथ गैर-आमने-सामने ग्राहक व्यवहार पर लागू होते हैं।
12. इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैध उम्मीदवारों को उनकी पहचान के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण क्रेडिट से वंचित करना नहीं है। परिचालन प्रबंधन द्वारा ग्राहक के उचित पहचान की वैकल्पिक प्रलेखित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ प्रबंधन / मुख्य परिचालन अधिकारी / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी अध्यक्ष की रिपोर्टिंग और अनुमोदन के अधीन होगा।

E. महत्वपूर्ण तत्व:

नीति घटक:

13. एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन उपाय और नियामक अनुपालन दोनों के रूप में केवाईसी नीति में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:
 - i. ग्राहक स्वीकृति मानदंड/नीति ("सीएपी");
 - ii. ग्राहक पहचान प्रक्रिया ("सीआईपी");
 - iii. जोखिम प्रबंधन; तथा
 - iv. लेनदेन की निगरानी।

(i) ग्राहक स्वीकृति मानदंड/नीति ("सीएपी"):

14. खाता संबंध स्थापित करने से पहले, ग्राहकों को इस नीति और विषय पर आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन की सुविधा के लिए उनके संविधान के आधार पर प्राकृतिक व्यक्ति या कानूनी इकाई/ इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
15. ग्राहक पहचान प्रक्रिया में उन दस्तावेजों को प्राप्त करना और सत्यापन शामिल होगा जो उन प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान और पता स्थापित करते हैं जो लाभकारी मालिक हैं।

16. प्रक्रिया का फोकस "भाग 1: (बी) नीति में प्रयुक्त परिभाषाएं" तालिका के तहत "लाभार्थी स्वामी" शब्द 4 में दर्शाए गए अनुसार लाभकारी मालिकों का आकलन करना होगा।
17. कंपनी खाता खोलने से पहले पूर्ण पैमाने पर ग्राहक की उचित पहचान (सीडीडी) करेगी। जब खाताधारक की सही पहचान ज्ञात नहीं होती है, तो कंपनी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग ("एसटीआर") दर्ज करेगी। कोई भी खाता फर्जी/गुमनाम/बेनामी नामों से या जहां कंपनी ग्राहक के असहयोग या ग्राहक द्वारा दिए गए दस्तावेजों/जानकारी की अविश्वसनीयता के कारण ग्राहक की उचित जांच करने में असमर्थ है, नहीं खोला जाएगा।
18. संयुक्त खाता खोलते समय सभी संयुक्त खाताधारकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
19. आरई यूसीआईसी (अद्वितीय ग्राहक पहचान कोड) स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया लागू करेंगे। इस प्रकार, यदि आरई का मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक उसी आरई के साथ दूसरा खाता खोलना चाहता है, तो नए सीडीडी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
20. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशों के आधार पर, आम जनता के सदस्यों, विशेष रूप से उन्हें, जो आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं, वित्तीय सुविधा से वंचित नहीं करेंगे। उचित सावधानी बरतते हुए, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अपनाई गई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी भी वास्तविक ग्राहक को सेवाओं से वंचित न किया जाए।

ii. ग्राहक पहचान प्रक्रिया ("सीआईपी"):

21. ग्राहक की पहचान का अर्थ है ग्राहक की पहचान करना और दस्तावेजों, डेटा या जानकारी के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत का उपयोग करके उसकी पहचान सत्यापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। कंपनी प्रत्येक ग्राहक की पहचान और व्यावसायिक संबंधों की इच्छित प्रकृति के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगी। कंपनी का मानना है कि सीआईपी अपने ग्राहकों को जानने का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे ग्राहक के लिए ऋण खाता खोलने की शुरुआत पर किया जाएगा। इसलिए सीआईपी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 और उसके तहत अधिसूचित संबंधित नियमों (पीएमएलए) के संदर्भ में कंपनी के लिए एएमएल (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) कार्यक्रम में एकीकृत किया गया है।
22. क्रेडिट अधिग्रहण/मूल्यांकन प्रक्रियाओं के अनुसार संभावित उधारकर्ताओं का ऋण प्रस्ताव अग्रेषण करते समय परिचालन प्रबंधन मूल के साथ तुलना करने के बाद दस्तावेजीकरण को प्रमाणित करेगा कि ग्राहक की पहचान और पते के संबंध में दस्तावेजीकरण प्राप्त किया गया है और केवाईसी नीति के अनुपालन के विशिष्ट संदर्भ के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है।
23. कोई क्रेडिट अनुमोदन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ग्राहक पहचान प्रक्रिया के संबंध में प्रमाणन की पुष्टि संबंधित परिचालन प्रबंधन कार्यकारी से प्राप्त नहीं कर ली जाती है।
24. कोई भी और सभी अपवाद, यदि सभी प्रदान किए जाते हैं, तो केवल प्रबंध निदेशक/क्रेडिट जोखिम प्रमुख द्वारा अनुमति दी जाएगी, उन कारणों और परिस्थितियों को लिखित रूप में दर्ज करना जिनके तहत ऐसे अपवादों की आवश्यकता/अनुमति दी गई थी। ऐसी अनुमतियों को तत्पश्चात् अंतराल पर समेकित तरीके से समीक्षा के लिए बोर्ड के पास रखा जाएगा।
25. ऐसे सभी मामलों में, ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं को इस तरह के अपवाद की अनुमति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा, किसी भी मामले में सात दिनों से कम के भीतर या ऋण के वितरण से पहले ऐसे अपवादों की अनुमति देने वाले प्राधिकरण और प्रधान अधिकारी को अनुपालन की सूचना दी जाएगी। ग्राहक पहचान आवश्यकताओं के लिए सांकेतिक मार्गदर्शन अनुबंध में दिए गए हैं।
26. ऐसे मामलों में जहां ग्राहक कंपनी की संतुष्टि के लिए ओवीडी प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वरिष्ठ प्रबंधन की संतुष्टि के लिए ग्राहक पहचान के वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जा सकता है, ग्राहक की उचित पहचान प्रक्रिया की 30 दिनों के भीतर समीक्षा के अधीन। ऐसे सभी ग्राहकों को उच्च जोखिम श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा और कम से कम -2-ऋण चक्र पूरा करने के लिए बढ़ी हुई उचित निगरानी के तहत रखा जाएगा।

ग्राहक उचित पहचान ("सीडीडी) प्रक्रिया

कंपनी के साथ लेन-देन करने वाले सभी ग्राहकों की सही पहचान को सत्यापित करने के लिए कंपनी उचित उपाय करेगी। कंपनी विशिष्ट उचित परिश्रम मानकों और प्रक्रियाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करेगी जो व्यवसायों, ग्राहकों और संबंधित जोखिमों की संबंधित प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त हैं। खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय, ग्राहक के प्रकार के आधार पर जिसके साथ इस तरह के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, निम्नलिखित उचित पहचान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा: इन प्रक्रियाओं में शामिल होंगे a) पहचान b) सत्यापन और c) विसंगति का समाधान।

ए) पहचान: ग्राहक के प्रकार के आधार पर पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

ग्राहक/ग्राहक	स्व-सत्यापित दस्तावेज
व्यक्ति (आवेदक/सह-आवेदक) - पहचान और पते का प्रमाण	1. **आधार के नामांकन के लिए पात्र और ग्राहक ने नामांकन किया है: a. जहां आधार नंबर सौंपा गया है;

	<ul style="list-style-type: none"> • आधार संख्या; • एक ताजा तस्वीर; तथा • दोनों में से कोई एक <ul style="list-style-type: none"> ▪ स्थायी खाता संख्या (पैन) या ▪ फॉर्म नंबर 60 <p>b. जहां आधार नंबर असाइन नहीं किया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • पूर्ववर्ती -6- (छह) महीनों के भीतर नामांकन के लिए आवेदन का प्रमाण; तथा • दोनों में से कोई एक <ul style="list-style-type: none"> ▪ स्थायी खाता संख्या (पैन) ▪ या ▪ फॉर्म नंबर 60; तथा ▪ पहचान और पते के विवरण वाले ओवीडी की प्रमाणित प्रति; तथा ▪ एक ताजा तस्वीर। <p>2. आधार नहीं बनाने वाले व्यक्ति - जम्मू और कश्मीर/मेघालय के व्यक्ति</p> <ul style="list-style-type: none"> • पहचान और पते के विवरण वाले ओवीडी की प्रमाणित प्रति; तथा • एक ताजा तस्वीर। <p>3. आधार के नामांकन के लिए पात्र नहीं व्यक्ति और अनिवासी:</p> <ul style="list-style-type: none"> • दोनों में से कोई एक <ul style="list-style-type: none"> ▪ स्थायी खाता संख्या (पैन) या ▪ फॉर्म 60 • एक ताजा तस्वीर; तथा • पहचान और पते के विवरण वाले ओवीडी की प्रमाणित प्रति • एक घोषणा कि व्यक्ति आधार के लिए पात्र नहीं है। <p>यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या या स्थायी खाता संख्या से संबंधित पहचान की जानकारी में वर्तमान पता नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए ग्राहक द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक ओवीडी (आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़) प्राप्त किया जाएगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. *पासपोर्ट; ii. ड्राइविंग लाइसेंस; iii. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; iv. राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड; <p>बशर्ते कि यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माना जाएगा:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. उपयोगिता बिल (किसी भी सेवा प्रदाता का -2- (दो) महीने से अधिक पुराना नहीं:
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ बिजली; ▪ टेलीफोन; ▪ पाइपड गैस; ▪ पानी का बिल; <p>ii. संपत्ति या नगर कर रसीद;</p> <p>iii. सरकारी कर्मचारियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को जारी पेंशन भुगतान या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है।</p> <p>iv. राज्य/केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक/नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी कर्मचारियों को आवास आवंटन या लीव एंड लाइसेंस समझौते का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव एंड लाइसेंस समझौते।</p> <p>बशर्ते कि ग्राहक उपरोक्त दस्तावेज जमा करने के 3 महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ आधार या ओवीडी जमा करें।</p> <p>*अनिवासी व्यक्तियों के मामले में अनिवार्य।</p> <p>** जहां आधार नामांकन और स्थायी खाता संख्या के लिए पात्र ग्राहक खाता-आधारित संबंध स्थापित करने की तारीख से छह महीने के भीतर आधार संख्या/पैन जमा करने में विफल रहता है, खाते में केवल जमा करने की अनुमति होगी जब तक ग्राहक द्वारा आधार कार्ड, पैन कार्ड/ फॉर्म 60 न जमा कर दिया जाये।</p> <p>नोट: यदि ओवीडी एक परिवर्तित नाम के साथ समर्थित है राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या विवाह के बाद नाम परिवर्तन का संकेत देने वाली राजपत्र अधिसूचना पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार की जाएगी।</p>
<p>कंपनियों के खाते</p> <ul style="list-style-type: none"> - कंपनी का नाम। - व्यापार का मुख्य केंद्र। - कंपनी का डाक पता। - टेलीफोन / फैक्स नंबर। 	<ul style="list-style-type: none"> • निगमन का प्रमाण पत्र और मेमोरेण्डम ऑफ़ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन; • खाता खोलने के लिए निदेशक मंडल का संकल्प और खाता संचालित करने का अधिकार रखने वालों की पहचान; • इसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को इसकी ओर से कारोबार करने के लिए दी गई मुख्तारनामा; • प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से लेनदेन करने के लिए एक वकील रखने के संबंध में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज; • पैन आवंटन पत्र की प्रति; • टेलीफोन बिल की प्रति;
<p>साझेदारी फर्मों के खाते</p>	<ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है; • साझेदारी विलेख; • फर्म के किसी भागीदार या कर्मचारी को उसकी ओर से व्यापार करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा; • भागीदारों और मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने वाला कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज; • फर्म/साझेदारों के नाम से टेलीफोन बिल।

ट्रस्टों और फाउंडेशनों के खाते – ट्रस्टियों, बसने वालों, लाभार्थियों और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम।	<ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण का प्रमाण पत्र, यदि पंजीकृत है; • न्यास विलेख; • उसकी ओर से कारोबार करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा; • ट्रस्टियों, बसने वालों, लाभार्थियों और पावर ऑफ अटॉर्नी, संस्थापकों / प्रबंधकों / निदेशकों और उनके पते रखने वालों की पहचान करने के लिए कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज; • फाउंडेशन/एसोसिएशन के प्रबंध निकाय का संकल्प; • टेलीफोन बिल
अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के खाते	<ul style="list-style-type: none"> • ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प; • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए उसे दिया गया मुख्तारनामा; • अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति के संबंध में एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज और ऐसी अन्य जानकारी जो कंपनी द्वारा ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकती है।
प्रोपराइटरशिप फॉर्म के लेखे संस्था के नाम, पते और गतिविधि का प्रमाण	<p>प्रोपराइटर पर लागू ग्राहक पहचान प्रक्रिया के अलावा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर निम्नलिखित में से कोई भी दो दस्तावेज पर्याप्त होंगे</p> <ul style="list-style-type: none"> • पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत उद्गम के मामले में) • दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस • बिक्री और आयकर रिटर्न • जीएसटी प्रमाणपत्र • बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज • आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा उद्गम को जारी किया गया / लाइसेंस / एक कानून के तहत शामिल किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा उद्गम के नाम से जारी प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र। • एकमात्र मालिक के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत। <p>ऐसे मामले में जहां कंपनी संतुष्ट है कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, उसके पास गतिविधि प्रमाण के रूप में उन दस्तावेजों में से केवल एक को स्वीकार करने का विवेक होगा। ऐसे मामलों में, हालांकि, कंपनी को संपर्क बिंदु सत्यापन करना होगा, ऐसी जानकारी एकत्र करनी होगी जो ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, पुष्टि करें, स्पष्ट करें और खुद को संतुष्ट करें कि व्यावसायिक गतिविधि स्वामित्व के पते से सत्यापित की गई है।</p>

कंपनी मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार आधार के लिए ऑफ़लाइन सत्यापन मोड के लिए जा सकती है। कंपनी इसके लिए बिजनेस कॉर्रेस्पॉण्डेंट (बीसी) की भी सेवाएं ले सकती है। हालांकि, यह केवाईसी दिशानिर्देशों पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुरूप होगा। वैकल्पिक रूप से “डिजिटल केवाईसी” के माध्यम से सत्यापन – 2016 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया और मास्टर निदेश 2016 में बाद के संशोधनों के साथ, ग्राहक की पहचान को ग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को कैप्चर करके सत्यापित किया जा सकता है जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ जहां मास्टर परिपत्र में निहित प्रावधानों के अनुसार आरई के अधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी लाइव फोटो ली गई है

बी) सत्यापन: कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राहक के साथ लेनदेन करने से पहले ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया जाना चाहिए। ग्राहक पहचान के सत्यापन के स्वीकार्य तरीकों में दस्तावेजों और/या गैर-दस्तावेजी सत्यापन विधियों के माध्यम से सत्यापन शामिल हो सकता है जो व्यवसाय की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिमों को देखते हुए उपयुक्त हैं।

बी1. दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन: कंपनी द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों में ग्राहकों से पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इन दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन दस्तावेजों की सूची तक सीमित नहीं हैं जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है। कंपनी के प्रतिनिधि, एकत्र किए गए ओवीडी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति की मूल के साथ तुलना करेंगे और प्रतिलिपि पर उसे रिकॉर्ड करेंगे।

बी 2. गैर-दस्तावेजी विधियों के माध्यम से सत्यापन: इन विधियों में निम्न शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

बी 2.1। किसी ग्राहक के पास जाना या उससे संपर्क करना:

बी2.2. उपभोक्ता रिपोर्टिंग एजेंसी, सार्वजनिक डेटाबेस या अन्य स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की तुलना के माध्यम से ग्राहक की पहचान को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना

बी 2.3। अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संदर्भों की जांच करना: या

बी 2.4. एक वित्तीय विवरण प्राप्त करना।

यदि एक पूर्ण केवाईसी सत्यापन एक शाखा, प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है और किसी खाते के लिए आवधिक अपडेशन के कारण नहीं है तो यह किसी अन्य शाखा/कार्यालय या कंपनी में स्थानांतरण के लिए मान्य है। सत्यापन डिजिटल केवाईसी के माध्यम से भी किया जा सकता है - जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, ग्राहक की लाइव फोटो उस स्थान के देशांतर और अक्षांश के साथ जहां ऐसी लाइव फोटो ली गई है और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज को कैप्चर करके ग्राहक की पहचान सत्यापित की जा सकती है, ।

3. विसंगतियों का समाधान:

यदि सही पहचान के संबंध में दस्तावेजों में जानकारी विसंगति है, तो कंपनी उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास करेगी। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो कंपनी ग्राहक के साथ व्यापार करने से मना कर सकती है।

बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया ("ईडीडी) प्रक्रिया

काशी कैपिटल मुख्य रूप से अपंजीकृत / बिना बैंक वाले / कम बैंक वाले ग्राहकों पर विशेष ध्यान देने के साथ सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के वित्तपोषण में लगी हुई है। आमतौर पर, जिन ग्राहकों की हम सेवा करते हैं, उनके प्रोफाइल में राजनीतिक भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के संभावित उच्च जोखिम नहीं होते हैं। एक सामान्य नियम के रूप में हम आम तौर पर ऐसे उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों के साथ लेन-देन नहीं करते हैं। हालांकि, यदि क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति या व्यवसाय संभावित रूप से उच्च जोखिम वाला है तो कंपनी बढ़ी हुई ड्यू डिलिजेंस का संचालन करेगी जिसमें मानक केवाईसी ड्यू डिलिजेंस के लिए आवश्यक अतिरिक्त उचित पड़ताल या जांच कार्रवाई शामिल होगी।

iii. जोखिम प्रबंधन:

27. इस नीति के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के ग्राहकों को जोखिम स्तर के आरोही चरणों में वर्गीकृत किया जाएगा। जोखिम श्रेणियां आम तौर पर और मोटे तौर पर जोखिम के कथित / निर्धारित स्तरों पर आधारित होंगी। , सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, स्थानीय विशेषताएं, मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी और गैर-दखल क्रेडिट जांच प्रक्रियाओं के दौरान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और/या प्राप्त की गई अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहक की पहचान स्थापित और सत्यापित की जाएगी। जहां कंपनी का मानना है कि नीचे उल्लिखित श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक विशेष ग्राहक एक अलग श्रेणी में पड़ने वाले श्रेणी में है, वह ग्राहक को श्रेणीबद्ध कर सकता है, जब तक कि ग्राहक फ़ाइल में उचित औचित्य प्रदान नहीं किया जाता है।
28. कंपनी के संचालन के इस शुरुआती चरण में, जोखिम वर्गीकरण के लिए तर्क यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी केवाईसी/एएमएल आवश्यकताओं के संबंध में कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बनी हुई है, जानबूझकर लक्षित ग्राहक जो अन्यथा वित्त प्रदान करने के योग्य हैं वित्त लेकिन औपचारिक क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल है, इन कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौतियों के कारण केवल ऋण तक पहुंच से वंचित नहीं हैं।
29. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत ग्राहकों की सूची उदाहरणात्मक है न कि संपूर्ण। वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर आगे विचार-विमर्श की आवश्यकता वाले सभी मामलों को क्रेडिट जोखिम के प्रमुख को भेजा जाएगा, जो वरिष्ठ प्रबंधन के परामर्श और उनके अनुमोदन से विचार-विमर्श के लिए उचित प्राधिकारी को वर्गीकरण के लिए संबंधित सलाह देते हैं। जोखिम वर्गीकरण में कोई भी संशोधन जो व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण आवश्यक हो सकता है, लेकिन नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों के भीतर, एक उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन समिति / नामित निदेशक द्वारा तय किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि संशोधन केवाईसी नीति में उपयुक्त संशोधन और समावेश के लिए बोर्ड के अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

30. ग्राहकों को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करना:

जोखिम स्तर (आरोही)	जोखिम श्रेणी	जोखिम विवरण	ग्राहक के उचित पहचान का स्तर खाता-आधारित संबंध शुरू करते समय - (ग्राहक ऑनबोर्डिंग)	बाद में अद्यतन
श्रेणी ए	कम जोखिम	<ol style="list-style-type: none"> 1. पूरी तरह से अनुपालन सीआईपी परिणाम और 2. सत्यापन पूर्ण और संतोषजनक; 3. खाते में परिचालन संतोषजनक; 4. व्यक्ति (उच्च निवल मूल्य के अलावा) और संस्थाएं जिनकी पहचान और धन के स्रोतों की आसानी से पहचान की जा सकती है और जिनके खातों में लेन-देन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफ़ाइल के अनुरूप है 5. समाज के निचले आर्थिक तबके के लोग जिनके खातों में कम टर्नओवर और छोटी शेष राशि दिखाई देती है 6. अच्छी तरह से परिभाषित वेतन संरचना वाले वेतनभोगी कर्मचारी 	जोखिम स्तर में परिवर्तन की आवधिक निगरानी/समीक्षा। जहां जोखिम के स्तर में कोई परिवर्तन होता है, वहां सीडीडी का स्तर जोखिम स्तर के अनुरूप होता है जिस पर ग्राहक के जोखिम में परिवर्तन हुआ है।	ऑनबोर्डिंग की तारीख से प्रत्येक -10- (दस) वर्ष। अद्यतन उस जोखिम स्तर/श्रेणी पर लागू किया जाएगा जहां ग्राहक स्थानांतरित हुआ है।
श्रेणी बी	मध्यम जोखिम	<p>सीआईपी परिणाम और सत्यापन कुछ अतिरिक्त प्रयासों के बाद पूरा हुआ लेकिन संतोषजनक; खाते में संचालन संतोषजनक लेकिन मध्यम स्तर पर चल रही निगरानी की आवश्यकता बताता है;</p> <ul style="list-style-type: none"> • उच्च नेटवर्थ वाले व्यक्ति (प्रति माह INR 1 करोड़ से अधिक की आय के रूप में परिभाषा) • गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान; • स्टॉक ब्रोकर्स; • आयातक/निर्यातक; • कंस्यूमर के व्यापारी; • इलेक्ट्रॉनिक्स में थोक डीलर; • अल्पज्ञात नोटरी और कानून फर्म 	वाणिज्यिक उधार के मामले में व्यापार संदर्भ जांच; यदि आवश्यक समझा जाए तो टेली सत्यापन करें।	ऑनबोर्डिंग की तारीख से प्रत्येक -8- (आठ) वर्ष।
श्रेणी सी	भारी जोखिम	<p>सीआईपी परिणाम और सत्यापन पूर्ण, लेकिन पहचान या पते के प्रमाण के प्रमाणीकरण में अंतर्निहित कठिनाइयां या केवाईसी पहलु के संबंध में क्रेडिट संदर्भ रिपोर्ट में चेतावनी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • विदेश वाले प्रवासी भारत, • पीईपी,(राजनीतिक रूप से सम्बंधित व्यक्तियों) • अनिगमित निकाय या ट्रस्ट), • पेशेवर बिचौलिये, • व्यक्तिगत रूप से सामने न आने वाले ग्राहक, 	निरंतर उचित पहचान और बेहतर निगरानी।	ऋण खाते के प्रत्येक नवीनीकरण/समीक्षा पर अद्यतन आवश्यक है।

		<ul style="list-style-type: none"> • प्राचीन वस्तुओं/हथियारों का व्यापार करने वाले ग्राहक, • स्लीपिंग पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप फर्म, • परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास, • केसिनो, • रियल्टर्स, ज्वैलर्स और इसी तरह के अन्य नकद गहन व्यवसायों में काम करने वाले ग्राहक। • ग्राहक जो क्रेडिट निर्णय के लिए प्रासंगिक स्तर पर संतोषजनक निवास/स्थान और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं। • अन्य सभी जो उपरोक्त 2 श्रेणियों में से किसी में शामिल नहीं हैं, जब तक कि उन्हें सीएपी और सीआईपी को संतुष्ट करने के आधार पर इनमें से किसी एक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। 	
--	--	--	--

iv. लेनदेन की निगरानी:

प्रभावी केवाईसी प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य तत्व निरंतर निगरानी है। खाते की जोखिम प्रोफाइल और जोखिम संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लेनदेन और इसकी सीमा की निगरानी की जाएगी। कंपनी ग्राहक की सामान्य और उचित गतिविधि को समझने का प्रयास करेगी ताकि नियमित/गतिविधि के पैटर्न से बाहर होने वाले लेनदेन की पहचान की जा सके। सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्यमान वैध उद्देश्य नहीं है। कंपनी किसी विशेष श्रेणी के खातों के लिए सीमा निर्धारित कर सकती है और इन सीमाओं से अधिक के लेन-देन पर विशेष ध्यान दे सकती है। ऐसे लेन-देन जिनमें बड़ी मात्रा में नकदी शामिल होती है जो ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि से असंगत होती है, विशेष रूप से कंपनी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। उच्च जोखिम वाले खातों की गहन निगरानी की जाएगी। कंपनी ऐसे खातों के लिए ग्राहक की पृष्ठभूमि, मूल देश, धन के स्रोत, शामिल लेनदेन के प्रकार और अन्य जोखिम कारकों के आधार पर प्रमुख संकेतक निर्धारित करेगी जो निगरानी की सीमा निर्धारित करेंगे। कंपनी आरबीआई वॉच लिस्ट सहित सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध विभिन्न वॉच लिस्ट के साथ नए खाता खोलने के आवेदनों को मान्य करने की संभावना का पता लगाएगी। वित्तीय सेवाओं से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की एक उदाहरणात्मक सूची अनुबंध II में दी गई है।

F. निरंतर निगरानी प्रक्रिया:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों का लेन-देन ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफाइल और निधियों के स्रोत के बारे में उनकी जानकारी के अनुरूप है, ग्राहकों की निरंतर निगरानी प्रक्रिया आवश्यक है:

- i. उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों के लेन-देन की निगरानी मध्यम/निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहकों की तुलना में अधिक गहनता से की जाएगी।
- ii. ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की वार्षिक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि ग्राहक की निरंतर निगरानी प्रक्रिया, ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण के लिए उपयुक्त रहती है।
- iii. ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर ग्राहक की निरंतर निगरानी प्रक्रिया का अद्यतन निम्नानुसार किया जाएगा:

जोखिम श्रेणी	आवधिक अद्यतन (कम से कम)	व्यक्तियों	कानूनी संस्थाएं
उच्च	-2- साल में एक बार	<ul style="list-style-type: none"> • पैन सत्यापन • आधार नंबर प्रमाणीकरण • यदि आधार में वर्तमान पता नहीं है तो वर्तमान पते वाला एक ओवीडी प्राप्त किया जा सकता है। 	खाता खोलते समय मांगे गए दस्तावेज और नई प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करें।

		<ul style="list-style-type: none"> पहचान और पते वाली ओवीडी की प्रमाणित प्रतियां आधार प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। 	
मध्यम	-8- साल में एक बार	<ul style="list-style-type: none"> पैन सत्यापन आधार नंबर प्रमाणीकरण यदि आधार में वर्तमान पता नहीं है तो वर्तमान पते वाला एक ओवीडी प्राप्त किया जा सकता है। पहचान और पते वाली ओवीडी की प्रमाणित प्रतियां आधार प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। 	खाता खोलते समय मांगे गए दस्तावेज और नई प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करें।
कम	-10- वर्षों में एक बार	<p>i. जहां पहचान और/या पते में कोई परिवर्तन होता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> पहचान और पते वाली ओवीडी की प्रमाणित प्रतियां; <p>ii. जहां पहचान और/या पते में कोई परिवर्तन नहीं होता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> इस आशय का स्व-प्रमाणन। 	खाता खोलते समय मांगे गए दस्तावेज और नई प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करें।

G. लाभार्थी स्वामी की पहचान:

हालांकि यह संभावना कम है कि कंपनी वैधानिक संस्थाओं के संबंध में नियमित आधार पर खाता-आधारित संबंध स्थापित करेगी, फिर भी ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय निगरानी/सावधानी के उपाय:

- कानूनी व्यक्ति जो एक प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लाभार्थी स्वामी (ओं) की पहचान की जाएगी और लाभकारी स्वामी (ओं) की पहचान को सत्यापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएंगे, सिवाय इसके कि ग्राहक या लाभकारी हित के मालिक (ओं) को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी या ऐसी सूचीबद्ध कंपनी की सहायक कंपनी।
- न्यासी खातों का ट्रस्ट/नामिती जहां ग्राहक ट्रस्टी/नामिती या किसी अन्य मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है और उन व्यक्तियों की जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं, कंपनी की संतुष्टि के लिए साक्ष्य, मध्यस्थ(यों), साथ ही ट्रस्ट की प्रकृति या अन्य व्यवस्थाओं का विवरण प्राप्त किया जाएगा।

H. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

कंपनी कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि कर्मचारियों के सदस्यों को केवाईसी/एएमएल/सीएफटी (आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला) प्रक्रियाओं में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके। नए ग्राहकों के साथ काम करने वाले फ्रंट लाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर अलग-अलग फोकस होना चाहिए ताकि सभी संबंधित लोग केवाईसी नीतियों के पीछे के तर्क को पूरी तरह से समझ सकें और उन्हें लगातार लागू कर सकें। ग्राहक शिक्षा की कमी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए फ्रंट-लाइन कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।

I. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन कार्य केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं का मूल्यांकन और अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। एक सामान्य नियम के रूप में, अनुपालन प्रक्रिया कानूनी और नियामक आवश्यकताओं सहित कंपनी की अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का एक स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करेगा। समिति की देखरेख में कंपनी का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि लेखा परीक्षा कार्य कुशल व्यक्तियों के साथ पर्याप्त रूप से कार्यरत है। आंतरिक लेखा परीक्षक विशेष रूप से शाखाओं में केवाईसी प्रक्रियाओं के आवेदन की जांच और सत्यापन करेंगे और इस संबंध में पाई गई खामियों पर टिप्पणी करेंगे। इस संबंध में अनुपालन उनकी सामान्य रिपोर्टिंग आवृत्ति के साथ समिति के समक्ष आगे रखा जाएगा।

J. रिकॉर्ड प्रबंधन:

पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक खाते की जानकारी के रखरखाव, संरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। कंपनी द्वारा,
 ए) लेनदेन की तारीख से कम से कम पांच साल के लिए, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों, कंपनी और ग्राहक के बीच लेनदेन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखें;

बी) खाता खोलते समय और व्यावसायिक संबंध के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड को व्यावसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम पांच वर्षों तक सुरक्षित रखें;

सी) अनुरोध पर सक्षम अधिकारियों को पहचान रिकॉर्ड और लेनदेन डेटा उपलब्ध कराएं;

डी) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम, 2005) के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने की एक प्रणाली शुरू करना;

ई) पीएमएल नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखें ताकि निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत लेनदेन के इतिहास को देखा जा सके:

ई (i)। लेनदेन की प्रकृति;

ई (ii) लेन-देन की राशि और वह मुद्रा जिसमें इसे मूल्यवर्गित किया गया था;

ई (iii) जिस तारीख को लेनदेन किया गया था; तथा

ई (iv) लेन-देन के पक्षकार ।

एफ) खाते की जानकारी के उचित रखरखाव और संरक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करना जिससे जब भी आवश्यक हो या सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर डेटा को आसानी से और जल्दी से पुनर्प्राप्त किया जा सके;

जी) अपने ग्राहक की पहचान और पते के रिकॉर्ड और नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में रिकॉर्ड हार्ड या सॉफ्ट प्रारूप में बनाए रखें।

K. फाइनेंसियल इंटेलिजेंस यूनिट- भारत

प्रधान अधिकारी नकद और संदिग्ध लेन-देन से संबंधित जानकारी, यदि पता चलता है, तो निदेशक, वित्तीय खुफिया इकाई भारत (एफआईयू-आईएनडी) को, जैसा कि पीएमएल नियमों के अनुसार सलाह दी गई है, आरबीआई द्वारा डिजाइन और परिचालित निर्धारित प्रारूपों में रिपोर्ट करेगा। कंपनी के कर्मचारी संदिग्ध लेनदेन के विवरण प्रस्तुत करने/रिपोर्ट करने के तथ्य की सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे।

L. जनरल:

I. नई प्रौद्योगिकियों का परिचय:

कंपनी किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग खतरों पर विशेष ध्यान देगी जो नई या विकासशील तकनीकों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें ऑनलाइन लेनदेन शामिल हैं जो गुमनामी का पक्ष ले सकते हैं, और यदि आवश्यक हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग में उनके उपयोग को रोकने के लिए उपाय करेंगे। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट, मेल/टेलीग्राफिक ट्रांसफर या किसी अन्य तरीके से धन का प्रेषण चेक से प्रभावित होता है न कि नकद भुगतान से ।

II. भारत के बाहर की शाखाओं और सहायक कंपनियों के लिए प्रयोज्यता:

यह नीति विदेशों में स्थित शाखाओं और अपने स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होगी, विशेष रूप से, उन देशों में जो एफएटीएफ की सिफारिशों को लागू नहीं करते हैं और जब कंपनी विदेशी शाखाएं खोलती है तो अपर्याप्त रूप से स्थानीय कानूनों की अनुमति देते हैं । जब स्थानीय लागू कानून और विनियम इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हैं, तो इसे आरबीआई के ध्यान में लाया जाएगा।

III. खातों को बंद करना/वित्तपोषण/व्यावसायिक संबंध की समाप्ति:

जहां कंपनी ग्राहक द्वारा जानकारी न देने और/या संचालन न करने के कारण उचित केवाईसी उपायों को लागू करने में असमर्थ है, कंपनी इस तरह के निर्णय लेने के कारणों को स्पष्ट करते हुए ग्राहक को उचित नोटिस जारी करने के बाद वित्त पोषण/व्यावसायिक संबंध समाप्त कर देगी। ऐसा निर्णय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के अनुमोदन से लिया जाएगा।

IV. मौजूदा खातों के लिए केवाईसी:

जबकि केवाईसी नीति सभी नए ग्राहकों पर लागू होगी, वही मौजूदा ग्राहकों पर भौतिकता और जोखिम के आधार पर लागू होगी। हालांकि, खातों के संचालन में किसी भी असामान्य पैटर्न के लिए मौजूदा ग्राहकों के साथ लेनदेन की लगातार निगरानी की जाएगी।

V. विविध मुद्दे:

कंपनी द्वारा प्रबंधन के उपयुक्त स्तरों पर निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाएगा:

- i. गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए, 1967) की धारा 51ए के अनुसार, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची में शामिल व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर कोई खाता नहीं खोला/संचालित/रखरखा जाए, जिनके आतंकवादी लिंक होने का संदेह है। जिन्हें निम्नलिखित -2- सूचियों के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर परिचालित किया जाता है:

- a) " आई ऐस आई अल (दाएश){ISIL(Daesh)} और अल-कायदा प्रतिबंध सूची" निम्नलिखित लिंक उपलब्ध है:
<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolved.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-quaida-r.xsl>
- b) "1988 प्रतिबंध सूची" निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolved.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-quaida-r.xsl>
- ii. 2 फरवरी, 2021 की यूएपीए अधिसूचना के तहत गृह मंत्रालय को सलाह देने के अलावा सूचियों में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते खातों के विवरण की सूचना एफआईयू-आईएनडी को दी जाएगी।
 - iii. उपरोक्त के अलावा, समय-समय पर किसी अन्य क्षेत्राधिकार/संस्थाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अन्य यूएनएससीआर पर भी ध्यान दिया जाएगा।
 - iv. गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के तहत संपत्तियों को फ्रीज करना: यूएपीए आदेश दिनांक 2 फरवरी, 2021 (मास्टर निदेश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015 का अनुबंध II) में निर्धारित प्रक्रिया -16 दिनांक 25 फरवरी, 2016 (10 मई, 2021 तक अद्यतन)) का कड़ाई से पालन किया जाएगा और सरकार द्वारा जारी आदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
 - v. कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45NB के तहत आवश्यक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगी।
 - vi. वरिष्ठ प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि केवाईसी डेटा को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ अनिवार्य रूप से साझा किया जाए, जैसा कि 'व्यक्तियों' और 'वैधानिक संस्थाओं' के लिए तैयार किए गए संशोधित केवाईसी टेम्प्लेट द्वारा आवश्यक है, जैसा भी मामला हो।
 - vii. परिचालन प्रबंधन के उपयुक्त स्तर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों पर आहरित ऋणों की अदायगी में प्राप्त चेक, यदि कोई हों, चेक की तारीख से -3 महीने के भीतर निपटान के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
 - viii. ऋण चुकौती में, ग्राहक के नाम पर अकाउंट पेयी चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 - ix. ₹ 50,000 और उससे अधिक के सभी नकद लेनदेन ग्राहक के पैन या फॉर्म 60 द्वारा होंगे।
 - x. आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान के मामले में (ग्राहकों की ओर से) आपूर्तिकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन) ग्राहक से प्राप्त किया जाएगा।
 - xi. जहां ग्राहक के पास पैन नहीं है, तो ग्राहक से फॉर्म 60 प्राप्त किया जाएगा।
- VI. कंपनी की केवाईसी नीति में अपडेट**
 प्रधान अधिकारी, समिति से उचित अनुमोदन लेने के बाद, केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति या कंपनी के ऐसे अन्य संबंधित मार्गदर्शन नोटों में समय-समय पर आवश्यक संशोधन/संशोधन करेगा, जो आरबीआई या ऐसे अन्य वैधानिक प्राधिकरण की आवश्यकताओं/अद्यतनों के अनुरूप होगा।

भाग III: अनुलग्नक

ग्राहक पहचान आवश्यकताएँ (सांकेतिक मार्गदर्शन)

अनुलग्नक I

1. भारत के बाहर निवासी राजनीतिक रूप से सम्बंधित व्यक्तियों (पीईपी) के खाते:

राजनीतिक रूप से सम्बंधित व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी विदेशी देश में प्रमुख सार्वजनिक गतिविधियों का काम सौंपा गया है, उदाहरण के लिए, राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकार/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के अधिकारी, आदि। शाखा / कार्यालय इस श्रेणी के किसी भी व्यक्ति / ग्राहक के संबंध में संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र करेगा और सार्वजनिक डोमेन में व्यक्ति पर उपलब्ध सभी सूचनाओं की जांच करेगा। पीईपी को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले शाखा/कार्यालय व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेगा और निधियों के स्रोतों के बारे में जानकारी मांगेगा। पीईपी के खाते में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का निर्णय वरिष्ठ स्तर पर लिया जाएगा और निरंतर आधार पर निगरानी की जाएगी।

2. कंपनियों और फर्मों के खाते:

शाखा/कार्यालय को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ खातों के रखरखाव के लिए, व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जा रही व्यावसायिक संस्थाओं के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। शाखा/कार्यालय इकाई के नियंत्रण ढांचे की जांच कर सकते हैं, धन के स्रोत का निर्धारण कर सकते हैं और उन व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं जिनके पास एक नियंत्रित हित है और जो प्रबंधन में शामिल हैं। इन आवश्यकताओं को जोखिम धारणा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों की पहचान करना आवश्यक नहीं होगा।

3. “पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक खाते” जब शाखा/कार्यालय के पास यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण होता है कि एक पेशेवर मध्यस्थ द्वारा खोला गया ग्राहक खाता एकल ग्राहक की ओर से है, तो ग्राहक की पहचान की जानी चाहिए। शाखा/कार्यालय म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या अन्य प्रकार के फंड जैसी संस्थाओं की ओर से पेशेवर मध्यस्थों द्वारा प्रबंधित 'पूल' खाते रख सकते हैं। शाखा/कार्यालय ग्राहकों की श्रेणी के लिए 'जमा पर' रखी गई निधियों के लिए वकीलों/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रबंधित 'पूल' खाते भी रखता है। जहां बिचौलियों द्वारा धारित निधियां शाखा/कार्यालय में एक साथ नहीं मिलती हैं और 'उप-खाते' हैं, और उनमें से प्रत्येक में एक लाभकारी स्वामी है तो सभी लाभकारी स्वामियों की पहचान की जानी चाहिए। जहां ऐसी निधियों को शाखा/कार्यालय में मिला दिया जाता है, शाखा/कार्यालय भी लाभार्थी स्वामियों को देखेंगे। जहां शाखा/कार्यालय एक मध्यस्थ द्वारा किए गए 'ग्राहक निरंतर निगरानी' (सीडीडी) पर निर्भर करता है, उन्हें स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मध्यस्थ विनियमित है और उचित रूप से केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त प्रणाली है। यह समझा जाना चाहिए कि ग्राहक को जानने की अंतिम जिम्मेदारी शाखा/कार्यालय की है।

अनुलग्नक II

वित्तीय सेवाओं से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की दृष्टान्त सूची

संदेह के कारणों की व्यापक श्रेणियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए संदिग्ध लेनदेन के उदाहरण निम्नानुसार दर्शाए गए हैं:

1. ग्राहक की पहचान:
 - a) गलत पहचान दस्तावेज
 - b) पहचान दस्तावेज जिन्हें उचित समय के भीतर सत्यापित नहीं किया जा सका
 - c) अन्य स्थापित व्यावसायिक संस्थाओं के बहुत करीब के नाम से खाते खोले गए।
2. ग्राहक की पृष्ठभूमि: संदिग्ध पृष्ठभूमि या ज्ञात अपराधियों के साथ संबंध।
3. एकाधिक खाते:

बड़ी संख्या में ऐसे खाते जिनके एक सामान्य खाताधारक, परिचयकर्ता हैं।
4. बिना किसी औचित्य के हस्ताक्षरकर्ता:
 - a) बिना किसी कारण के एकाधिक खातों के बीच अस्पष्टीकृत स्थानान्तरण।
5. खातों में गतिविधि:
 - a) पिछले लेनदेन की तुलना में असामान्य गतिविधि- निष्क्रिय खातों में अचानक गतिविधि;
 - b) घोषित व्यवसाय से जो अपेक्षित होगा, उससे असंगत गतिविधि।
6. लेनदेन की प्रकृति:
 - a) असामान्य या अनुचित जटिलता;
 - b) कोई आर्थिक औचित्य या वास्तविक उद्देश्य नहीं;
 - c) नकदी के साथ ड्राफ्ट या अन्य परक्राम्य लिखतों की बार-बार खरीद;
 - d) लेन-देन की प्रकृति, घोषित व्यवसाय से अपेक्षित अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।
7. लेनदेन का मूल्य:
 - a) रिपोर्टिंग से बचने के एक स्पष्ट प्रयास में रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड राशि के ठीक नीचे मूल्य।
 - b) ग्राहक की स्पष्ट वित्तीय स्थिति के साथ असंगत मूल्य।
8. संदिग्ध लेनदेन की निदर्शी सूची:
 - a) सूचना, डेटा और दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के लिए अनिच्छुक;
 - b) झूठे, दस्तावेज, ऋण का उद्देश्य और खातों का विवरण जमा करना;
 - c) प्रारंभिक अंशदान की निधियों के स्रोत का विवरण प्रस्तुत करने में अनिच्छा;
 - d) व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनिच्छा, मुख्तारनामा के माध्यम से प्रतिनिधित्व करना;
 - e) अपने पते से दूर एक दूर की शाखा के पास जाना;
 - f) स्पष्टीकरण के बिना एकाधिक खाते बनाए रखना;
 - g) असंबंधित तृतीय-पक्ष खाते के माध्यम से प्रारंभिक योगदान का भुगतान;
 - h) ऋण की मंजूरी के लिए संदिग्ध साधनों का सुझाव देना;
 - i) जहां लेनदेन का आर्थिक अर्थ नहीं है;
 - j) जहां लाभकारी स्वामित्व के बारे में संदेह हो;
 - k) एक फर्जी बैंक खाते के माध्यम से ऋण का नकदीकरण;
 - l) लेन-देन से कोई संबंध नहीं रखने वाले तीसरे पक्ष के पक्ष में भुगतान का अनुरोध;
 - m) विक्रेताओं, या एजेंट के साथ मिलीभगत से निर्धारित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण राशि का उपयोग;
 - n) एनजीओ, चैरिटेबल संगठन, छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त समूहों, आदि को शामिल करते हुए कई फंडिंग;
 - o) पते में परिवर्तन के लिए बार-बार अनुरोध;
 - p) अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने के अनुरोध के साथ किशतों का अधिक भुगतान।
 - q) एक कर्मचारी जिसकी भव्य जीवन शैली को उसके वेतन या आय के ज्ञात स्रोतों द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता है